

संख्या: 236971 / XV-1/23-1(7)19/26187

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 03 सितम्बर, 2024

विषय: पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) योजना के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके ई पत्र संख्या-28233/2024/नि-5/एक(4)/एस्कैड/2024-25 दिनांक 23 अगस्त, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता योजनान्तर्गत स्पेशल एवं ड्राईबल पक्ष में अवमुक्त 100 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि क्रमशः रु० 0.91 लाख एवं रु० 0.47 लाख अर्थात् कुल धनराशि रु० 1.38 लाख (रु० एक लाख अड़तीस हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न विवरणानुसार प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

अनु. संख्या	लेखाशीर्षक	बजट प्रावधान	अवमुक्त धनराशि
30	2403-पशुपालन-00-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष एटक योजना-01-केन्द्र सहायतित योजना-01-पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (100प्र.के.स.)-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एसएनए में अन्तरण	3.64	0.91
31	2403-पशुपालन-00-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-01-केन्द्र सहायतित योजना-01-पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (100प्र.के.स.)-14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एसएनए में अन्तरण	1.88	0.47
	योग-	5.52	1.38

- धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-८ पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जाए और न अधिक व्ययभार सृजित किया जाए।

4. वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु रप्ट योजना बना ली जाये और तदनुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।
5. प्रशासनिक / बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के रूप पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग-1, बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।
6. स्वीकृत / अवमुक्त की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता, दुरुपयोग, दोहरीकरण (Doubling) एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
7. इस संबंध में रप्ट किया जाता है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग भारत सरकार को प्रेषित कार्य योजना के अनुसार ही किया जाय तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
8. योजनान्तर्गत सामग्री की आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईड लाईन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-30 एवं अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत उपरोक्त लेखाशीर्षकों के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 201358 / 09(150)2019 / XXVII(1) / 2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Signed by Rajendra Kumar भवदीय,

Bhatt

Date: 03-09-2024 14:44:36 (भ्रष्टेन्द्र कुमार भट्ट)

संयुक्त सचिव

संख्या: 236971 (1) / XV-1/23-1(7)2019 / 26187 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, कूमार्यू मण्डल / गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाइल।

Signed by Mahaveer Singh आज्ञा से,
Parmaar

Date: 03-09-2024 15:23:24

(महावीर सिंह परमार)
उप सचिव